SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will it be a Central project or will the State also contribute something?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: It is a Central project with foreign collaboration.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Would you link it up with the iron ore reserves in Calicut?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: No, Sir.

Industrial Cables (India) Limited

*552. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 778 on the 16th November, 1972 and state:

(a) whether the Office of M|s Industrial Cables (India) Limited in New Delhi has violated the Bonus Ordinance by paying only 4 per cent Bonus for the year ending 31st October, 1971 to its ex-employees; and

(b) whether the Central Government are collecting this information for legal action against this firm?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) and (b). As already stated in reply to Unstarred Question No. 778 on the 16th November, 1972, the matter falls in the State sphere. It is for the Government of Punjab to verify the complaint and take such action as may be deemed necessary. The matter has been brought to their notice.

कुमारी कमला कुमारी : इनका सारा आफिस दिल्ली में है, लेकिन इसकी जांच करने के लिये हमें राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ रहा है—यह कैसी बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही है ? जब आप के कर्मचारी जांच के लिये जीवन-तारा बिल्डिंग गये तो उनको खिला पिला कर वापस लौटा दिया बात और उन्होंने यहां लिख कर भेज दिया कि यह राज्य सरकार से सम्बन्धित मामला है—यह बात समझ में नहीं आती है। व राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार उनको 14 परसेन्ट बोनस मिलना चाहिये, तो उनको 4 परसेन्ट बोनस दिया गया, यदि आप चाहें तो मैं उन कर्मचारियों को पेश कर सकती हू जिन्हें 4 परसेन्ट बोनस मिला है—यह कैसी बात है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्रीमन्, इसमें कम्पनी का हेड आफिस राजपुरा पजाब में स्थित है इसलिये पजाब गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एथारिटी होने के नाते से कार्यवाही कर सकती है। हां, उनका आफिस एक दिल्ली मे है और हमारे मंत्रालय ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की है और उनसें मालूम हुआ है कि मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) लिमिटेड ने अपने एम्प्लायर्ज को 4 परसेन्ट के हिसाब से बोनस दिया है और 10 परसेन्ट के हिसाब से एक्सग्रेशिया पेमेन्ट इस साल किया है। बाकी इसके रिकार्ड्स जो हैं वह राजपुरा में मेनटेन होते हैं इसलिये उसके बारे में कोई सूचना नही है, हमने पजाब गवर्नमेंट को इसके बारे में लिखा है (व्यवधान)।

कुमारी कमला कुमारी : मैं माननीय मत्री महोदय से जानना चाहती हु कि कितने लोगो को 4 परसेन्ट दिया गया और क्यो दिया गया और अभी तक इसके बारे में आपने पूरी जांच कराई है या नहीं ? अगर नही कराई है तो क्यो नही कराई है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैंने कहा कि 4 परसेन्ट दिया गया है और वर्तमान इम्पलाईज को 10 परसेन्ट एक्स-ग्रेशिया भी दिया है। इस के बारे में हमने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है। क्योंकि वह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसलिये उनको चाहिये कि आवश्यक कार्यवाही करें, यदि कोई उल्लंघन किया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Reduction in Retirement Age of workers

*548. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to reduce the age of retirement of workers to 50 years and allow the benefits in order to ease the unemployment in the country except in some exceptional cases like the Rsearch cadres; and

(b) if so, the main points thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) (a) No, Sir.

(b) . Does not arise.

Ratio of Promotion between Promoters and Direct Recruits

*553. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to put the ratio of Officers selected through direct recruitment and those through promotion on at least fifty-fifty basis; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No, Sir.

(b). Does not arise.

भारत और इसरायल "पड़ोसी" राष्ट्रों के लिए संभावित शक्तिशाली आणविक खतरे

*554. श्री सूरजभान वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और सोवियत संघ के संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा दो वर्ष तक किए गए अध्ययनों के बाद दोनो देशों के संयुक्त हस्ताक्षरों से वाशिंगटन में एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जिसमें "पड़ोसी राष्ट्रो के लिये संभावित शक्तिशाली खतरों"के रूप में भारत और इजरायल के नामों का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). अमरीका की संयुक्त राष्ट्र संस्था और सोवियत संघ की संयुक्त राष्ट्र संस्था ने एटमी हथियारों के अधिक उत्पादन के प्रश्न पर समानान्तर अध्ययन का प्रकाशन कर दिया है। ये अध्ययन उन विभिन्न संभव समर्थक उपायो से सम्बन्धित है जिनका उद्देश्य अणु-अस्त्र अनुत्पादन संधि को सुदृढ़ करने और उस संधि का अधिक समर्थन प्राप्त करना है। अमरीका की संयुक्त राष्ट्र सस्था की रिपोर्ट में भारत तथा इजराइल को अत्यन्त महत्व के दो 'प्रवशकारी' देश बताया गया है जिन्होंने अणु-अस्त्र अनुत्पादन संधि पर हस्ताक्षर नही किये है। सोवियत सघ सयुक्त राष्ट्र सस्था की रिपोर्ट मे भारत का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है लेकिन इजराइल के बारे मे केवल इतना कहा गया है कि उस पर प्रभाव डालना चाहिये और अणु-अस्त्र अनुत्पादन संधि पर उसका समर्थन सर्वप्रथम प्राप्त करना चाहिये ।

भारत सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है कि उसकी नीति अणु-शक्ति का केवल शातिपूर्ण उपयोग करने के लिये है ।

Expenditure on Meetings of C.B.T. of E.P.F. Organisation

*555. SHRI BHOLA MANJHI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether a heavy expenditure is being incurred for holding the C.B.T. meetings of E.P.F. organisation; specially in the places of sight-seeing like Simla Ooty, Goa and Darjeeling;